(3)

मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्वों

भारत में मुद्रा की पूर्ति निर्धारिक करने वाले तत्वों तथा उसमें परिवर्तन के स्रोतो के विश्लेषण में रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के किसी स्पष्ट सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता रहा है। यह मुद्रा के पूर्ति में परिवर्तन को केवल लेखांकन या वास्तविक स्थिति का विश्लेषण तथा इन परिवर्तनों को उत्पन्न करने वाले तत्वों या स्रोतो के विषय में विवेचन करता है।

रिजर्व बैंक अपने विश्लेषण में उच्च शक्ति मुद्रा की संख्याएं प्रदान करता है किन्तु वस्तुतः देश में मुद्रा की कुल पूर्ति की गणना करने के लिए यह सामान्य मुद्रा को उच्च शक्ति मुद्रा के साथ मिला देता है और इस लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करने वाले महत्व पूर्ण तत्व के रूप में उच्च शक्ति मुद्रा को उचित महत्व प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक दो व्यवहारवादी अनुपातों अर्थात जनता के वांछित करेंसी अनुपात (K) एवं बैंकों के नकद कोष अनुपात (R) पर भी मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्वों के रूप में ओर रहे देता है यद्यपि इन अनुपातों की वास्तविक संख्याएं प्रदान करता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्वों को भिन्न चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।

P.T.O

(1) बैंकिंग प्रणाली से सरकारी उधार लेना।

(2) बैंकिंग प्रणाली से निजी अथवा व्यापारिक क्षेत्र का उधार लेना।

(3) भुगतान संतुलन की स्थिति में परिवर्तन के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की विशुद्ध विदेशी परिसम्पत्तियों में परिवर्तन।

(4) जनता को सरकार की करेंसी देयताएँ।

(1) सरकार को बैंक साख :→ जब सरकारी व्यय सरकार की आय की अपेक्षा अधिक हो जाता है तथा सरकार अपने व्यय में कमी करने में असमर्थ होती है। या अनिच्छुक होती है तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से उधार लेती है। इस उद्देश्य से नये करेंसी नोट का सृजन करता है। केन्द्रीय सरकार के बजट के घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए नई करेंसी का यह सृजन घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है।

अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। सरकार सामान्य व्यापारिक बैंकों से भी ऋण लेती है। जब बैंक सरकार को उधार देते हैं तो वे साख का सृजन नहीं करते हैं। जब बैंक सरकार के लिए साख का सृजन करते हैं तो उनके द्वारा मांग का सृजन अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर देती है।

(2) निजी या व्यापारिक क्षेत्र को बैंक साख → जब निजी क्षेत्र के अपने संसाधन कुल व्यय से कम होते हैं तो वह भी बैंकिंग प्रणाली से उधार लेता है।

P.T.O.

BNMU

क्योंकि जब बैंक उधार देते हैं तो वे साख के सृजन करते हैं। यद्यपि बैंकिंग प्रणाली से सरकार द्वारा उधार लेने के समान ही मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है। इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि यद्यपि सरकार देश के केन्द्रीय बैंक से लगभग अनिवार्य रूप से उधार ले सकती है, किन्तु निजी क्षेत्र बैंकों से ऐसा नहीं कर सकता है।

(3) विशुद्ध विदेशी विनिमय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन :→ रिजर्व बैंक द्वारा रखी गई विदेशी विनिमय परिसम्पत्ति में परिवर्तन भी मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन ला सकते हैं। विशुद्ध विदेशी परिसम्पत्तियों में परिवर्तन भुगतान संतुलन की स्थिति द्वारा उत्पन्न हो सकता है। माना कि भुगतान संतुलन विपरीत या प्रतिकूल है और इसलिए उपलब्ध विदेशी विनिमय दृश्य और अदृश्य दोनों आयातों के भुगतान के लिए देश की आवश्यकता की अपेक्षा कम है।

इस प्रकार विपरीत व्यापार संतुलन को पूरा करने के लिए देश को अपनी कुछ विदेशी विनिमय परिसम्पत्ति को बेचना पड़ेगा। यदि विशुद्ध भुगतान संतुलन घाटा है तो रुपये का रिजर्व बैंक में प्रवाह होगा और उसके बदले में विदेशी

P. T. O

BNMU

विनिमय का भुगतान करता है। भारत में इसके चलते में करेंसी को कम करते तथा जनता में मुद्रा की पूर्ति का संकुचन करने का प्रभाव होगा। जब देश का विश्व भुगतान संतुलन अनुकूल होता है तो इसके विपरीत परिणाम होंगे।

(4) जनता को सरकार की करेंसी देयताएं :→ जनता को सरकार की करेंसी देयताएँ का दायित्व होता है। सरकार जनता को करेंसी देयताओं की कानूनी गारंटी लेती है। जनता के पास करेंसी का अर्थ प्रचलन में मुद्रा का कुल स्टॉक (कागजी नोट, सिक्के और बैंक की मांग जमा) है जो किसी विशेष समय पर जनता के पास होता है।

भुगतान संतुलन में घाटा अर्थव्यवस्था में रुपया करेंसी की पूर्ति को व्यक्त करता है तथा उसके द्वारा जनता में मुद्रा की पूर्ति में संकुचन उत्पन्न करता है। इसके विपरीत भुगतान संतुलन में अतिरिक्त विदेशी विनिमय परिसम्पत्तियों में वृद्धि करेगा तथा उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में देशी करेंसी तथा मुद्रा की पूर्ति में विस्तार करेगा। भुगतान संतुलन की अतिरिक्त विदेशी विनिमय कोष या परिसम्पत्तियाँ विदेशी सहायता या अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में जमा या भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा किए गए विनियोग के माध्यम से आ सकता है।

P.T.O

भारतीय अर्थव्यवस्था में स्फीति-कारी दबाव उत्पन्न कर रही है। अब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति से कमी उत्पन्न करती है। जिससे समस्त मांग में कमी होती है। वस्तुओं के आयात से पूर्ति में वृद्धि होती है। जो कीमत को कम करने में सहायता करती है।